SECTION WISE WORK IN REVENUE DEPARTMENT

शाखा	आवंटित कार्य
1 समन्वय शाखा	समन्वय, सचिवालयीन स्टाफ/विधानसभा, जिला, संभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्थापना, विभागीय नस्तियां/कोटवारों की सेवा शर्ते एवं उससे संबंधित कार्य/डाक वितरण।
2A शाखा	कृषि भूमि के नियमन तथा प्रबंधन से संबंधित संपूर्ण कार्य, भू–राजस्व संहिता की धारा 239 के अंतर्गत पट्टे संबंधी कार्य, जमीदारी उन्मूलन विधान एवं इसी प्रकार के अन्य भू–सुधार नियमों के कार्य, राजस्व पुस्तक परिपत्र–4(3) में संबंधित कृषि भूमि के आवंटन विषयक वासस्थान दखलकार अधिनियम तथा दखलरहित भूमि विशेष उपबंध अधिनियम, वन भूमि व्यवस्थापन (वन भूमि के पट्टे) कृषि भूमि उच्चतम सीमा अधिनियम, आबादी एवं ग्रामीण आवास योजना, नेमनूक भुगतान, राजगामी संपदा, मध्यप्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा, 1960 के तहत अतिशेष घोषित भूमि का बंटन उसका मुआवजा। जमीदारी–जागीरदारी उन्मूलन विधान, ऋण पुस्तिका, अभिलेख प्रमाण पत्र, निस्तार एवं वाजिवल अर्ज, वन भूमि व्यवस्थापन, भू–दान बोर्ड, ग्रामदान, पड़त भूमि अधिकार अभियान, हरिजन आदिवासियों के भूमि संरक्षण संबंधित कार्य, अपर कलेक्टर की शक्ति प्रदान करना।
2B शाखा	नजूल भूमि आवंटन/प्रबंधन राजस्व पुस्तक परिपत्र 4–1, आवास नीति, नजूल संधारण।
3 शाखा	राहत, राजस्व पुस्तक 6(4), कृषि मजदूर फसल व मौसम पूर्वानुमान
4A शाखा	समस्त राजस्व अधिकारियों (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) कर्मचारियों की स्थापना/प्रशिक्षण व सतर्कता आदि/परामर्शदात्री समिति, नियंत्रण मुद्रण लेखन सामग्री की स्थापना से संबंधित समस्त कार्य
4Bशाखा	आयुक्त भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त की स्थापना/प्रशिक्षण व उनके कार्यकलापों की व्यवस्था।
5 शाखा	पटेली कमीशन में वृद्धि तथा पटेली से संबंधित अन्य समन्वय, बजट एवं लेखा योजना संबंधी कार्य, जिलों में वाहन, दूरभाष, समर्पण, पुर्नविनियोजन, राजस्व अनुभाग, तहसील तथा उप तहसील हेतु बजट प्रावधान, कार्यालय भवन, राजस्व वसूली, निरीक्षण प्रतिवेदन, प्रारूप कंडिका, एजीएमपी से प्राप्त प्रतिवेदन, आडिट आक्षेप, लोक लेखा समिति, नए जिलों/नए तहसीलों के भवन निर्माण, निरीक्षण, वित्त आयोग।
6 शाखा	भू–परिमापन एवं बंदोबस्त तथा सर्वेक्षण, अधिकार अभिलेख, जिला, तहसील–उप तहसील पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट, हल्का बंदी, मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता में संशोधन, राजस्व ग्राम संपादित करने का कार्य, चकबंदी, शहरों तथा ग्रामों के नाम परिवर्तन, अंतर्राज्यीय सीमा संबंधी विवाद/डायवर्सन, ग्रामीण ऋण, समस्त राजस्व प्रकरणों का निराकरण एवं उससे संबंधित अभियान/चलित न्यायालय/राजस्व न्यायालय का निरीक्षण, ऋण पुस्तिकाओं संबंधित कार्य/भू–अभिलेख का कम्प्यूटराजेशन, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, फसल सांख्यिकी योजना, जमीनों की प्रमाणिक दरों का निर्धारण, टोपोशीट, नामांतरण बटवारा एवं सीमांकन, तहसीलदार एवं सहायक बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां प्रदान करना, मंदिरों के भूमि विवाद संबंधित न्यायालयीन प्रकरण, पंचायतों के अधिकार।